

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 010/2012 (GCMS 2012/00035)	दायर दिनांक 03.09.2012	निर्णय दिनांक 15.06.2022
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीप्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी
विभागीय प्रतिनिधि

राजकीय अधिवक्ता
अप्रार्थी

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू-प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 199 रकबा 11.00 हैक्टेयर बने जिसमें से आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में शिक्षा विभाग, चित्तौड़गढ़ के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर जो शिक्षा विभाग चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 10.04.1989 से दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरुद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये हैं जिसके अनुसार मौके



की व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर उक्त आराजी शिक्षा विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर माननीय न्यायालय राजस्थाई हाई कॉर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेटा दर्ज की जावें।

इस पर प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.10.2012 को अप्रार्थी की और से विभागीय प्रतिनिधि हाजिर आये जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने बताया कि संस्थान राजकीय शिक्षण संस्थान है जिसका प्रबंधन शिक्षा विभाग राजस्थान के अधीन है। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप जिले में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय (डाईट) के रूप में विकसित करने हेतु जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ की मांग पर जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक-राजस्व/ 12-3(55)87/2882 दिनांक 18.12.1987 से आराजी नंबर 199 में से 10 एकड भूमि इस संस्थान को निःशुल्क आवंटित की गई। इसी प्रकार जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(55)87/ 510-15 दिनांक 31.03.1989 से आराजी नंबर 199 में से 5 एकड भूमि और आवंटित की गई है। उक्त आवंटन आदेशों की पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विधिवत इस संस्थान को भूमि का कब्जा सौंपा गया है। विधिवत् कब्जा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित बजट एवं निर्देशों के अनुरूप डाईट प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन पुरुष एवं महिला छात्रावास एवं आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कराया गया। वर्तमान में डाईट भवन में विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप करवाये जा रहे हैं। छात्रावास में छात्राध्यापक रहते हैं। यह संस्थान राजकीय कार्यालय होने से भूमि का खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के पास ही है कोई निजी खातेदार इस भूमि पर काबिज नहीं है, ऐसी अवस्था में आवेदन चलने योग्य नहीं है। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 15.06.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू-प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 199 रकबा 11.00 हैक्टेयर बने जिसमें से



आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में शिक्षा विभाग, चित्तौड़गढ़ के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर जो शिक्षा विभाग चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 10.04.1989 से दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरुद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेडा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये हैं। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप जिले में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय (डाईट) के रूप में विकसित करने हेतु जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ की मांग पर जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक-राजस्व/12-3(55)87/2882 दिनांक 18.12.1987 से आराजी नंबर 199 में से 10 एकड़ भूमि इस संस्थान को निःशुल्क आवंटित की गई। इसी प्रकार जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(55)87/510-15 दिनांक 31.03.1989 से आराजी नंबर 199 में से 5 एकड़ भूमि और आवंटित की गई है। उक्त आवंटन आदेशों की पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विधिवत इस संस्थान को भूमि का कब्जा सौंपा गया है। विधिवत् कब्जा प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित बजट एवं निर्देशों के अनुरूप डाईट प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन पुरुष एवं महिला छात्रावास एवं आवासीय क्वार्ट्स का निर्माण पी.डब्ल्यू. डी. के माध्यम से कराया गया। वर्तमान में डाईट भवन में विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप करवाये जा रहे हैं। छात्रावास में छात्राध्यापक रहते हैं। यह संस्थान राजकीय कार्यालय होने से भूमि का खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के पास ही है कोई निजी खातेदार इस भूमि पर काबिज नहीं है। ऐसी अवस्था में आवेदन चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि परिपत्र दिनांक 16.07.2003 की पालना में जोहड़, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते हैं। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05



हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेठा दर्ज की जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मीठारामजी का खेडा पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की वर्तमान आराजी संख्या 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर भूमि किस्म गे.मु. दर्ज रिकार्ड होकर शिक्षा विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो नियमों के विरुद्ध है, नियमानुसार किस्म गे.मु. भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपटित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :-

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239



राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा किस्म तालाब पेटा होकर बिलानाम मेवाड बंदोबस्त में दर्ज है। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 199 रकबा 11.00 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसमें से आराजी नंबर 199 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा आराजी नंबर 494/199 रकबा 4.05 हैक्टेयर जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में शिक्षा विभाग, चित्तौड़गढ़ के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इस बाबत नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 10.04.1989 एवं नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 21.04.1989 शिक्षा विभाग चित्तौड़गढ़ के नाम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म तालाब पेटा की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को ख़ातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा प्रावधान निम्न प्रकार है :-

16 Land on which Khatedari rights shall not accrue-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों से संबंधित तत्कालीन समय का संपूर्ण राजस्व रिकार्ड और खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके बिना इस भूमि के संबंध में किसी विधिसंगत निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात संवत् 2018 में राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित रही है, उसके पश्चात्



कालान्तर में उक्त आराजीयात खातेदारी अधिकारों से दर्ज अभिलिखित की गई है। प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त हस्तगत प्रकरण में संवत् 2018 का ही रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात् विवादित आराजीयात का अन्तरण किस प्रकार से हुआ है, प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित किया एवं ना ही इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, ऐसी स्थिति प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय/अधिकारियों द्वारा लिए गए विवादित निर्णयों/आदेशों की विधिकता, नियमितता एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :-

- विवादित भूमि का संवत् 1993 के पश्चात् किस प्रकार से आवंटन/नियमन किया गया है एवं इस संबंध में संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर यह निर्धारित करे कि प्रश्नगत आवंटन व नामान्तरकरण प्रक्रिया नियमानुकूल, वैध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?
- विवादित भूमि के जलोट या जलीय निकाय की होने की स्थिति की जांच आवंटन के समय के रेकार्ड एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर किया जावे। समस्त दस्तावेजों, अभिलेख व तथ्यों के साथ आवश्यक हो तो, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिसमें अपेक्षित/संबंधित अभिलेख जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हो एवं अधिनियम की धारा 232 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र बोलता हुआ (SELF SPEAKING) के रूप में "Reasoned and speaking" हो प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 15.06.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़